

Daily करेंट अफेयर्स

➤ 19 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. IBM और महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।



अगस्त 2025 में, इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन्स (IBM) कॉर्पोरेशन ने महाराष्ट्र सरकार के साथ राज्य के क्वांटम कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में IBM के इंडिया क्लाउंट एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन के दौरान इस समझौते को औपचारिक रूप दिया गया।

- आशय पत्र (LoI) का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को समर्थन देकर भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महाराष्ट्र की स्थिति को मज़बूत करना है। यह सहयोग राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के साथ संरेखित होगा, जो भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए बनाई गई एक पहल है।

- IBM महाराष्ट्र को अपने राज्य-स्तरीय क्वांटम कंप्यूटिंग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और उसे लागू करने में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। यह पहल नवाचार और अनुसंधान के लिए एक मज़बूत ढाँचा तैयार करने पर केंद्रित होगी और साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकियों में वैश्विक अग्रणी बनने के भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का भी समर्थन करेगी।

- इस सहयोग में कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास गतिविधियाँ शामिल होंगी जिनका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग में एक मज़बूत प्रतिभा पूल का निर्माण करना है। ये प्रयास न केवल रोज़गार सृजन में मदद करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र के तकनीकी परिदृश्य में एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के उद्भव में भी सहायक होंगे।

Key Points:-

(i) मुंबई में नवनिर्मित IBM इंडिया क्लाउंट एक्सपीरियंस सेंटर इस साझेदारी में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। यह केंद्र वाटसनएक्स प्लेटफॉर्म, डेटा और ऑटोमेशन, साइबर सुरक्षा, हाइब्रिड क्लाउड और भारतीय व्यवसायों के लिए अनुकूलित परामर्श-आधारित समाधानों के माध्यम से AI पर ध्यान केंद्रित करेगा।

(ii) इस आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके, महाराष्ट्र सरकार और IBM ने क्वांटम अनुसंधान, कौशल विकास और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत के व्यापक दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष योगदान देगा।

2. लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित किया, जिससे भारत के समुद्री भविष्य के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई।



लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित किया, जो भारत के समुद्री प्रशासन में एक बड़े सुधार का प्रतीक है। इस विधेयक का उद्देश्य बंदरगाह संचालन का आधुनिकीकरण, व्यापार दक्षता को बढ़ावा देना और वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करना है। यह पुराने औपनिवेशिक नियमों को प्रतिस्थापित करता है और भविष्य के लिए तैयार, विश्वस्तरीय समुद्री क्षेत्र के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- विधेयक में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की स्थापना का प्रस्ताव है। MSDC समुद्री विकास में समन्वय स्थापित करेगा और बंदरगाहों, उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का सुचारू समाधान सुनिश्चित करेगा। इस कदम से दीर्घकालिक बंदरगाह नियोजन के लिए संस्थागत समर्थन बढ़ने की उम्मीद है।

- इस विधेयक का एक प्रमुख आकर्षण व्यापार सुगमता (EoDB) में सुधार पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। यह बंदरगाह प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, परिचालनों का डिजिटलीकरण करता है, हरित पहलों को शामिल करता है, और आपदा प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ बनाता है। यह पारदर्शी टैरिफ ढाँचे को अनिवार्य बनाता है और उच्च सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है, जिससे भारत एक प्रतिस्पर्धी समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित होता है।

Key Points:-

(i) इस विधेयक से माल की आवाजाही को सुव्यवस्थित करके और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आने का अनुमान है। इससे परिचालन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और संबद्ध उद्योगों जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा के

उपयोग के प्रावधान भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को बल देंगे।

(ii) यह विधेयक बंदरगाहों को एक पारदर्शी प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से शुल्क निर्धारित करने की अनुमति देकर उनकी स्वायत्तता को भी बढ़ावा देता है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों और बहुविध परिवहन प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होता है। इससे निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के आकर्षित होने और बुनियादी ढाँचे के विकास को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।

(iii) केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "समृद्धि के लिए बंदरगाह" के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति में बदलना है। विधेयक भारत के बंदरगाहों को आर्थिक विकास, वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा और सतत विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में स्थापित करता है।

3. MoPR ने ग्राम सभा सारांशों को डिजिटल बनाने के लिए AI-पावर्ड टूल 'सभासार' लॉन्च किया।



पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने ग्राम सभा और पंचायत रिकॉर्डिंग से स्वचालित रूप से संरचित बैठक

कार्यवृत्त (MoM) तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सारांश उपकरण 'सभासार' लॉन्च किया है। इस पहल का शुभारंभ अगस्त 2025 में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा किया गया था।

- सभासार टूल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) तकनीकों का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है, जिससे मौखिक चर्चाओं का स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन, प्रमुख निर्णयों की पहचान और सुव्यवस्थित सारांश तैयार करना संभव हो जाता है। यह टूल भारत के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) भाषिणी के साथ एकीकृत है, ताकि बहु-भाषाओं में पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

- इस शुभारंभ समारोह में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्य पाल सिंह बघेल ने भाग लिया, जिन्होंने स्थानीय शासन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाने में इसके महत्व पर जोर दिया।

- पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ग्राम सभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए सभासार टूल अपनाने का आग्रह किया है।

Key Points:-

(i) पहले चरण के तहत, त्रिपुरा को प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए चुना गया था। 15 अगस्त 2025 को, त्रिपुरा की सभी 1194 ग्राम पंचायतों—जिनमें पारंपरिक स्थानीय निकाय भी शामिल हैं—ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ विशेष ग्राम सभाओं के लिए MoM तैयार करने हेतु इस उपकरण का उपयोग किया। यह जमीनी स्तर पर डिजिटल सशक्तिकरण पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।

(ii) जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया भाषिणी, भारत का AI-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफ़ॉर्म है और वर्तमान में 13 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है,

और इसमें और भाषाओं को जोड़ने की योजना है। सभासार के साथ अपने एकीकरण के माध्यम से, यह प्लेटफ़ॉर्म विविध भाषाई क्षेत्रों के पंचायत पदाधिकारियों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करता है, जिससे सहभागी लोकतंत्र मज़बूत होता है।

(iii) सभासार के प्रमुख उद्देश्यों में कार्यकुशलता बढ़ाना, मैनुअल दस्तावेज़ीकरण पर लगने वाले समय को कम करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और पंचायत अधिकारियों को शासन और सेवा वितरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना शामिल है। ग्राम सभा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करके, सरकार का लक्ष्य ई-गवर्नेंस, ग्रामीण डिजिटल नवाचार और सहभागी निर्णय लेने में एक नया मानदंड स्थापित करना है।

4. भारतीय रेलवे ने वाराणसी के BLW में पटरियों के बीच पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का अनावरण किया।



15 अगस्त 2025 को, रेल मंत्रालय (MoR) ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW), वाराणसी, उत्तर प्रदेश में रेलवे पटरियों के बीच भारत की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली शुरू की, जो भारतीय रेलवे (IR) के तहत टिकाऊ हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

● पायलट परियोजना का उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस 2025 को BLW की लाइन नंबर 19 पर किया गया। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और शुद्ध-शून्य कार्बन तटस्थता के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा एक अभिनव पहल का प्रतिनिधित्व करता है।

● इस सौर प्रणाली की स्थापित क्षमता 15 किलोवाट पीक (kWp) है, जिसमें 70 मीटर लंबे ट्रैक पर फैले 28 पैनल शामिल हैं। यह मॉड्यूलर डिज़ाइन ट्रेन संचालन में बाधा डाले बिना स्थापना, निष्कासन और रखरखाव को आसान बनाता है।

Key Points:-

(i) इस परियोजना से प्रति किलोमीटर सालाना लगभग 3.21 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा की उल्लेखनीय बचत होगी। यह प्रणाली प्रतिदिन प्रति किलोमीटर 880 यूनिट ऊर्जा घनत्व भी प्रदान करती है, जिससे टिकाऊ बिजली उत्पादन सुनिश्चित होता है।

(ii) 220 kWp प्रति किलोमीटर की ऊर्जा घनत्व के साथ, यह परियोजना सीमित रेलवे ट्रैक स्थानों में भी नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करती है, तथा एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिसे बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा अपनाने के लिए पूरे देश में दोहराया जा सकता है।

BANKING & FINANCE

1. NSIC ने MSME ऋण पहुँच बढ़ाने के लिए निजी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) ने हाल ही में MSMEs क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत MSME के लिए ऋण उपलब्धता, अंतिम-मील कनेक्टिविटी और विकास समर्थन को मजबूत करने के लिए पांच निजी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

● NSIC द्वारा अगस्त 2025 में एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटक बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक सहित निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

● यह पहल MSME ऋण सुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करने और औपचारिकीकरण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

● NSIC के निदेशक (वित्त) गौरव गुलाटी ने NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) डॉ. एस. एस. आचार्य और सहभागी बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। इस कार्यक्रम में MSMEs के लिए ऋण पहुँच को बढ़ावा देने हेतु NSIC और बैंकों के बीच सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

Key Points:-

(i) हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - MoMSME) तथा एस.सी.एल. दास, सचिव, MoMSME भी उपस्थित रहे, जिसने भारत में एमएसएमई (MSME) के लिए ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

(ii) प्रत्येक सहभागी बैंक क्षेत्रीय क्षमता का उपयोग करता है: एक्सिस बैंक (मुंबई), धनलक्ष्मी बैंक (त्रिशूर), कर्नाटक बैंक (मैंगलोर), एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (जयपुर), और इंडसइंड बैंक (मुंबई)। एनएसआईसी के साथ उनके सहयोग का उद्देश्य राज्यों में छोटे उद्यमों के लिए औपचारिक वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

(iii) इन समझौता ज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य MSME की ऋण पहुँच को बढ़ाना, अंतिम छोर तक वित्तपोषण प्रदान करना और क्षेत्र के विकास एवं औपचारिकीकरण में तेज़ी लाना है। MSMEs को औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों से जोड़कर, यह पहल छोटे व्यवसायों को अपनी पहुँच बढ़ाने, ऋण अंतराल को कम करने और भारत के आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद करेगी।

ECONOMY & BUSINESS

1. ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती बढ़ने से जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो जाएगी।



सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर हाल ही में जुलाई 2025 में घटकर 5.2% हो गई, जो जून में 5.6% थी। यह सुधार मुख्य रूप से कृषि से जुड़े मज़बूत ग्रामीण रोज़गार और श्रम बल में बढ़ती भागीदारी के कारण हुआ है।

● जुलाई में ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 4.4% रह गई, जो जून में 4.9% थी, जो फ़सल कटाई और त्यौहारी सीज़न से पहले मज़बूत मौसमी भर्तियों को दर्शाती है। इस बीच, शहरी बेरोजगारी थोड़ी बढ़कर 7.2% हो गई, जो रोज़गार वृद्धि में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाती है।

● 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं में ग्रामीण बेरोजगारी 13.8% से घटकर 13.0% हो गई, जबकि शहरी युवा बेरोजगारी 18.8% से बढ़कर 19.0% हो गई, जो शहरी नौकरी बाजारों में लगातार चुनौतियों का संकेत है।

Key Points:-

(i) श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जून में 54.2% से बढ़कर जुलाई में 54.9% हो गई, जो कार्यबल में बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है - जो समावेशी रोज़गार सुधार के लिए एक उत्साहजनक संकेत है।

(ii) 2025 के आरंभ से, भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) को नया रूप दिया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक श्रम बाजार डेटा जारी करना संभव हो गया है, और नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए विस्तृत, समय पर जानकारी उपलब्ध हो गई है।

(iii) बेरोजगारी में गिरावट व्यापक आर्थिक लाभ के साथ मेल खाती है: भारत सरकार विनिर्माण और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर तक GST में कटौती की योजना बना रही है। इस बीच, बढ़ते व्यापार विवादों के बीच मज़बूत विकास और अनुशासन का हवाला देते हुए, S&P ने भारत की

सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है।

2. NTPC विद्युत आपूर्ति के लिए ISO 22301:2019-आधारित व्यवसाय निरंतरता योजना अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया।



अगस्त 2025 में, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी, NTPC लिमिटेड (जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), भारतीय बिजली क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के ISO 22301:2019 वैश्विक मानक के अनुरूप व्यवसाय निरंतरता योजना (BCP) अपनाने वाली पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) बन गई। यह योजना निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और भारत के ऊर्जा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- NTPC ने भारत में बिजली निरंतरता के लिए औपचारिक रूप से व्यवसाय निरंतरता योजना को अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बनकर एक मानक स्थापित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसका संचालन लचीला बना रहे।

- अपनाया गया ढांचा ISO 22301:2019 पर आधारित है, जो व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली

(BCMS) के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो तत्परता, रोकथाम, समन्वित प्रतिक्रिया और महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतर सुधार पर जोर देता है।

- यह पहल निर्बाध बिजली उत्पादन और आपूर्ति की गारंटी देने के लिए तैयार की गई है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक विश्वसनीय रीढ़ के रूप में एनटीपीसी की भूमिका मजबूत होगी और औद्योगिक और घरेलू दोनों बिजली मांगों का समर्थन होगा।

Key Points:-

(i) BCP में आवधिक जोखिम आकलन, आपदा पुनर्प्राप्ति अभ्यास, बैकअप संचार चैनल और समन्वित प्रतिक्रिया रणनीतियां शामिल हैं, जो कर्मचारियों, परिसंपत्तियों और महत्वपूर्ण विद्युत अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

(ii) इस कदम के साथ, NTPC का लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में उभरते जोखिमों का समाधान करना, निरंतर निगरानी और सुधार के लिए प्रणालियां शुरू करना है, जिससे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा लचीलापन मजबूत हो सके।

(iii) NTPC द्वारा इस वैश्विक मानक को अपनाना, भारत द्वारा अपने सार्वजनिक उद्यमों के आधुनिकीकरण के प्रयासों को दर्शाता है। इस तरह के ढाँचे को अपनाने वाले पहले सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, एनटीपीसी विद्युत एवं अवसंरचना क्षेत्र के अन्य संगठनों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

MOUs and Agreement

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और C-DAC ने डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 'ई-सुश्रुत@क्लिनिक' लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



अगस्त 2025 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईआईटीवाई) के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक) ने आउट पेशेंट क्लिनिकों के लिए एक हल्के, क्लाउड-आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) 'ई-सुश्रुत@क्लिनिक' लॉन्च करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (DoHFW), MoHFW की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य सेवा समाधानों के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

- ई-सुश्रुत@क्लिनिक एक किफायती और सरकार समर्थित HMIS समाधान है, जिसे विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहुंच को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह प्रणाली सितंबर 2021 में शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य एक अंतर-संचालनीय राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

Key Points:-

(i) यह प्लेटफॉर्म बाह्य रोगी प्रबंधन, फार्मसी और नर्सिंग मॉड्यूल के लिए तैयार किया गया है, साथ ही यह डिजिटल रोगी रिकॉर्ड को सक्षम बनाता है और टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदान करता है।

(ii) स्वास्थ्य सेवा प्रदाता स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR) और स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (HPR) के माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं, जिससे संस्थानों और व्यक्तिगत चिकित्सकों दोनों का समावेश सुनिश्चित हो सकेगा।

(iii) यह प्लेटफॉर्म उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए AIIMS क्लिनिकल डिजीजन सपोर्ट सिस्टम (CDSS) के साथ एकीकृत है, जबकि इसे पहले से ही देश भर में 17 AIIMS और 4,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लागू किया जा रहा है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. अभिनव बिंद्रा को खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए IOC मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया।



अगस्त 2025 में, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष, अभिनव बिंद्रा को IOC के मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका काम एथलीटों के मानसिक स्वास्थ्य की

वकालत करना और शिक्षा और सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से कलंक को तोड़ना था।

- IOC मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में, अभिनव बिंद्रा आठ अन्य ओलंपियनों के साथ खेलों में मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए शामिल हुए हैं। उनका मिशन एक ऐसा सहायक वातावरण बनाना है जहाँ एथलीट मदद लेने के लिए प्रोत्साहित महसूस करें और जहाँ मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक फिटनेस जितना ही महत्वपूर्ण माना जाए।

- बिंद्रा की नियुक्ति IOC की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना के अनुरूप है, जिसे उच्च-प्रदर्शन वाले खेल वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंबेसडर विश्वसनीय व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, IOC की पहलों पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, और विश्व स्तर पर एथलीट समुदाय के बीच खुले संवाद को प्रेरित करते हैं।

Key Points:-

(i) IOC इस बात पर ज़ोर देता है कि “मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है।” बिंद्रा जैसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों पर खेलों में मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से जुड़े कलंक को तोड़ने, शैक्षिक कार्यक्रमों, सोशल मीडिया आउटरीच और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से सहायता प्रदान करने का दायित्व है।

(ii) भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता (बीजिंग 2008, 10 मीटर एयर राइफल) बिंद्रा लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य के मुखर समर्थक रहे हैं। राजदूत के रूप में नियुक्ति से पहले, वह IOC मानसिक स्वास्थ्य कार्य समूह के सदस्य भी थे। उनकी व्यक्तिगत यात्रा—जो उपलब्धियों के बाद की चुनौतियों से भरी रही है—उनके मार्गदर्शन और प्रचार-प्रसार को विश्वसनीयता प्रदान करती है।

(iii) बिंद्रा विभिन्न विषयों और महाद्वीपों के सात अन्य

ओलंपियनों की वैश्विक सूची में शामिल हो गए हैं, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन के होली ब्रैडशॉ, हांगकांग के कैमिली चेंग, ब्राजील के ब्रूनो फ्रेटस, USA के ग्रेसी गोल्ड, आइवरी कोस्ट के मैरी-जोसी ता लू-स्मिथ, पापुआ न्यू गिनी के रयान पिनी, दक्षिण अफ्रीका के अकानी सिम्बाइन और अफगानिस्तान के मासोमा अली जादा शामिल हैं।

SPORTS

1. भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा।



भारत 20 से 23 अगस्त तक ओलंपिक-मानक हिमाद्री आइस स्केटिंग रिक, देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। यह आयोजन भारतीय खेलों में एक ऐतिहासिक क्षण है, जो शीतकालीन खेलों के मंच पर देश के उदय को रेखांकित करता है।

- भारत पहली बार प्रतिष्ठित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है—जो देश के शीतकालीन खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस चैंपियनशिप में देहरादून के हिमाद्री आइस स्केटिंग रिक, जो भारत का एकमात्र ओलंपिक-स्तरीय सुविधा केंद्र है, में 10 से ज्यादा एशियाई देशों के शीर्ष स्केटर्स हिस्सा लेंगे।

- 20-23 अगस्त 2025 तक चलने वाला यह चार दिवसीय आयोजन देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा - जो देश का एकमात्र ओलंपिक आकार का रिक है।

Key Points:-

- इसमें 10-11 देशों के लगभग 240 स्केटर्स और अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिनमें चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और अन्य देशों की टीमों शामिल हैं।
- प्रतियोगी जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों में 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले तक की नौ दौड़ दूरियों में भाग लेंगे, जिसमें गति, धीरज और टीम गतिशीलता का प्रदर्शन किया जाएगा।
- आयोजकों का मानना है कि यह चैंपियनशिप भारत में शीतकालीन खेलों के बुनियादी ढाँचे के विकास में उत्प्रेरक का काम कर सकती है। इससे आइस रिक, प्रशिक्षण सुविधाओं और युवा एथलीट विकास कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं—जैसे जूनियर विश्व कप (2027 तक), 2029 एशियाई खेल, और भविष्य में शीतकालीन ओलंपिक—की मेजबानी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

2. पूर्व श्रीलंकाई घरेलू क्रिकेटर सलिया समन पर पांच साल के लिए सभी तरह के क्रिकेट से प्रतिबंध लगा दिया गया।



श्रीलंका के पूर्व घरेलू ऑलराउंडर सलिया समन को ICC भ्रष्टाचार रोधी न्यायाधिकरण द्वारा 2021 अबू धाबी T10 लीग के दौरान मैच में हेरफेर के प्रयास में अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद पांच साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

● समन पर अब बंद हो चुकी पुणे डेविल्स फ्रैंचाइज़ी के तहत 2021 अबू धाबी T10 लीग में मैचों में हेरफेर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। ट्रिब्यूनल ने उन्हें ECB भ्रष्टाचार निरोधक संहिता की धारा 2.1.1, 2.1.3 और 2.1.4 के उल्लंघनों का दोषी पाया, जिसमें फिक्सिंग के प्रयास, पुरस्कार की पेशकश और भ्रष्ट आचरण के लिए उकसाना शामिल है।

● उन्हें सभी प्रकार के क्रिकेट से पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, तथा निलंबन की तारीख 13 सितंबर 2023 है, जिस दिन उन्हें अनंतिम रूप से निलंबित किया गया था।

Key Points:-

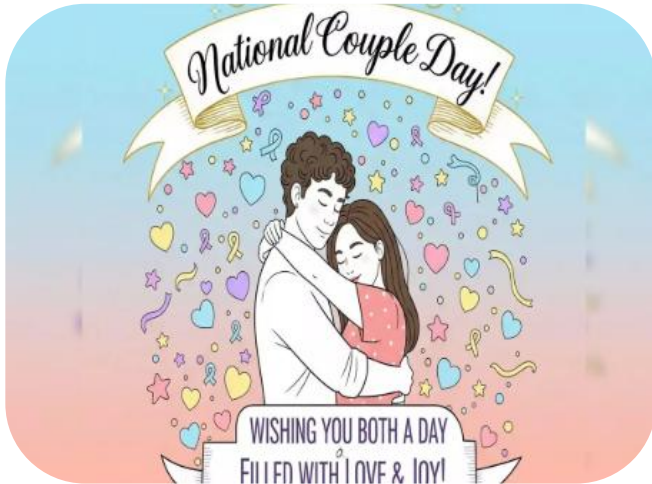
- समन उन आठ लोगों में से एक हैं जिन पर सितंबर 2023 में आरोप लगाए गए थे, जिनमें बांग्लादेश के ऑलराउंडर नासिर हुसैन, टीम के अधिकारी और अबू धाबी T10 लीग से जुड़े कोचिंग स्टाफ शामिल हैं।
- एक अनुभवी ऑलराउंडर, समन ने 101 प्रथम श्रेणी, 77 लिस्ट A और 47 T20 घरेलू मैच खेले हैं।

उनका आखिरी ज्ञात प्रदर्शन मार्च 2021 में SLC ट्वेंटी20 टूर्नामेंट में था।

(iii) यह अनुशासनात्मक कार्यवाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की मैच फिक्सिंग से निपटने और क्रिकेट में, विशेष रूप से फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंटों में, ईमानदारी बनाए रखने की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

IMPORTANT DAYS

1. राष्ट्रीय युगल दिवस 18 अगस्त 2025 को मनाया गया।



राष्ट्रीय युगल दिवस प्रतिवर्ष 18 अगस्त को मनाया जाता है, जो पूरे अमेरिका में युगलों के बीच प्रेम, साहचर्य और भावनात्मक बंधन का जश्न मनाता है। हालांकि इसकी वास्तविक जड़ें अनौपचारिक हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस दिन को पहली बार 2010 के आसपास वेलेंटाइन डे से अलग रोमांटिक रिश्तों का सम्मान करने के लिए मनाया गया था।

● हालाँकि सटीक विवरण कम हैं, लेकिन सर्वोत्तम अनुमान बताते हैं कि राष्ट्रीय युगल दिवस की शुरुआत 2010 में हुई थी, संभवतः एक अमेरिकी कंपनी ने रिश्तों के हल्के-फुल्के उत्सव के रूप में इसे शुरू किया था। समय के साथ, यह स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ और सोशल मीडिया तथा

लोकप्रिय संस्कृति की पहलों के माध्यम से लोकप्रिय हुआ।

● कई परिवर्तनशील छुट्टियों के विपरीत, राष्ट्रीय युगल दिवस हर साल 18 अगस्त को पड़ता है, चाहे वह सप्ताह का कोई भी दिन हो। इसका उद्देश्य वेलेंटाइन डे के छह महीने बाद, जोड़ों को सार्थक व्यवहार और साथ बिताए समय के माध्यम से अपने रिश्तों को पहचानने और संजोने का एक और अवसर प्रदान करना है।

Key Points:-

(i) यह दिवस सभी प्रकार की साझेदारियों को शामिल करता है—समलैंगिक, विपरीत लिंग और गैर-पारंपरिक संबंधों सहित। जैसे-जैसे प्रेम के बारे में सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं, राष्ट्रीय युगल दिवस एक समावेशी प्रतीक बन गया है कि सभी का बंधन उत्सव मनाने का हकदार है।

(ii) इस दिन को मनाने के लोकप्रिय तरीकों में शामिल हैं, दिल को छू लेने वाले प्रेम पत्र, रोमांटिक डिनर (घर पर या बाहर), सरप्राइज़ पिकनिक, "लव जार" और व्यक्तिगत फ़ोटो एल्बम। आर्थिक रूप से मामूली लेकिन भावनात्मक रूप से समृद्ध भाव अक्सर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं—यह दर्शाते हुए कि प्रेम विलासिता से कम और ईमानदारी से ज़्यादा जुड़ा है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. भारतीय नौसेना ने कोलकाता में GRSE द्वारा निर्मित तीसरा सर्वेक्षण पोत 'Ikshak' शामिल किया।



(ii) Ikshak के शामिल होने से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों में भारत की क्षमता मजबूत होगी, जिससे रक्षा और समुद्री व्यापार सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक नेविगेशन, चार्टिंग और समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययनों में सहायता मिलेगी।

-
- 11

Static GK

Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : कमोडोर PR हरि	मुख्यालय : कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
International Business Machines (IBM)	CEO : अरविंद कृष्णा	मुख्यालय: अरमोंक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)	स्थापना : 1988	मुख्यालय: पुणे
National Small Industries Corporation Limited (NSIC)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD): डॉ. एस. एस. आचार्य	मुख्यालय: नई दिल्ली
NTPC Limited	स्थापना: 1975	मुख्यालय: नई दिल्ली
Emirates Cricket Board (ECB)	अध्यक्ष: वासबर्ट ड्रेक्स	अध्यक्ष: शेख नहयान मबारक अल नहयान
Indian Railways (IR)	मंत्री: अश्विनी वैष्णव	मुख्यालय: नई दिल्ली
International	अध्यक्ष:	मुख्यालय:

Olympic Committee (IOC)	किर्स्टी कोवेंट्री	लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
--------------------------------	--------------------	----------------------